श्रम विभाग

श्रादेश

दिनांक 30 जुलाई, 1984

सं. स्रो. वि./म्रध्वाला/13-84/26887.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं (1) नियंत्रक, हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़ (2) महा प्रवन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, ग्रम्बाला शहर के श्रमिक श्री राकेश कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद खिखित मामले मैं कोई भ्रौद्योगिक विवाद है;

घ्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, श्रीद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 की धारा 10की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रीधसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 श्रप्रेल, 1984 द्वारा उना श्रीधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, श्रम्बाला को विवादप्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला व्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रीमक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रथवा सम्बन्धित मामला है:—

ृ क्या श्री राकेश कुमार की सेवार्यों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ग्रो.वि./ग्रम्बाला/96-84/26894.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० पौलीकास्ट स्पन 'पाईप, चण्डी मन्दिर (ग्रम्बाला) के श्रमिक श्री धंम पाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है;

'ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाता को विवाद अस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निविष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद अस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :--

. क्या श्री र्धम पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं श्रो वि /श्रम्बाला / 150-84/26900.---चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं पाइन पैक्स प्रा कि , 188, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, पंचकूला, जिला श्रम्बाला के श्रमिक श्री मुख्तयार सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई भीधोगिक विवाद है;

भोर पूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, भौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हैरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 3(44)-84-3श्रम, दिनांक 19 श्रप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री मुख्तवार सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. श्रो.वि./श्रम्बाला/107-84/26906.—चृति हरियाणा के राज्यपाल की राज्यपाल की नन्योला को-मोपरेटिब कडिट सोसाईटी लि॰ नन्योला (श्रम्बाला) के श्रामिक श्री गुरद्याल सिंह तथा ससके प्रवासकों के मध्य इसमें इसके बाद जिल्लिय नामने में कोई भौदोनिक विवाद है:

मीर चूंकि हरियाणा के राज्यवाल विवाद को 'न्यायिनिर्णय हेतु निर्विष्ट करना विक्रिय समझते हैं;

इतिल्ए, अब, भी बोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 मप्रैल, 1984 द्वारा उक्त श्रिधिनियम की धारा 7 क श्रिधीन गठित श्रम न्यायालय, श्रम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रष्वा सम्बन्धित मामला है :∸−

क्या श्री गुरदयाल सिंह की सेवामों का समापन न्यायाचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राह्त का हकदार है ?

्दिनांक 31 जुलाई, 1984

सं 0 श्रो 0िव 0 | पानीपत | 7.1 | 84 | 27455. — चूिक हिरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं 0 पैन्सीयान एजैंन्सी, राम नगर, तहसील कैम्प पानीपत के श्रमिक श्री क्षाम नरायण पंडित तथा उसके प्रवत्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्री छोगिक विवाद है;

श्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रोद्योगिक विवाद श्रिष्टिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिनियम, का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिष्टिस्चना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 श्रप्रैल, 1984 द्वारा उक्त श्रिष्टिनियम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, श्रम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री राम नरायण पंडित की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं श्रो वि । पानीपन | 21 | 84 | 27 461 — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की रायें है कि मैं सुपर रवड़ इन्टरप्राईजिज, 17 | 3 माईल स्टोन, जी. टी. रोड, करनाल के श्रीमक श्री वी रमान तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है ;

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को त्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, श्रौद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरहारी श्रिधिसूचना सं० 3(44)-84-3-श्रम, दिनांक 19 श्रप्रैल, 1984 द्वारा उक्त श्रिधिनियम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, श्रम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय- निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रयवा संबंधित मामला है :—

नयां श्री वीरभान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं0 श्रो 0िव 0/पानोपत/ 19/84/27467.—चूंकि हिरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं 0 सुपर रखड़ इन्टरश्राईजिज, 17/3, माईल स्टोन, जी टी रोड़, करनाल के श्रमिक श्रो दीनानाथ तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है:—

श्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा भामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :--

क्या श्री दीनानाथ की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?